[2017] 7 एस.सी.आर. 228

भारतीय फार्मेसी परिषद

बनाम

डॉ. आत्माराम दरियानी और अन्य

(2017 की सिविल अपील संख्या 8382)

03 जुलाई, 2017

[जगदीश सिंह खेहर, सीजेआई, एन. वी. रमना और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.जे.]

फार्मेसी एक्ट, 1948 की धारा 30, 31, 32 - क्या नया राज्य छत्तीसगढ़ धारा 30 के तहत प्रथम रजिस्टर की तैयारी के लिए पंजीकरण न्यायाधिकरण का गठन करने के लिए सक्षम है; और क्या पंजीकरण न्यायाधिकरण उन फार्मासिस्टों के पंजीकरण के नवीनीकरण के कार्य को करने के लिए सक्षम था जो पहले से ही पूर्ववर्ती राज्य मध्य प्रदेश के पहले रजिस्टर में शामिल हैं - निर्णय: मध्य प्रदेश के पूर्ववर्ती राज्य द्वारा तैयार किया गया पहला रजिस्टर नए राज्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए पहले रजिस्टर के रूप में माना जाएगा - पहले रजिस्टर को मध्य प्रदेश के पूर्ववर्ती राज्य द्वारा तैयार किया गया था, उसे पंजीकरण के समय फार्मासिस्टों द्वारा दिए गए आवासीय पते के साथ क्षेत्रीय संबंध के आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए - वे फार्मासिस्ट जो शिक्षा विनियमन लागू होने से पहले मध्य प्रदेश के पूर्ववर्ती राज्य के पहले रजिस्टर में पंजीकृत हैं और जो उस राज्य में अभ्यास नहीं करना चाहते जहां उनका आवासीय पता है, वे अधिनियम की धारा 32(2) के अनुसार दूसरे राज्य में पंजीकरण कर सकते हैं - ऐसे फार्मासिस्ट जिनके नाम मध्य प्रदेश के पूर्ववर्ती राज्य द्वारा तैयार पहले रजिस्टर में पंजीकृत थे, उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य में अधिनियम की धारा 32(2) के तहत औपचारिक रूप से पंजीकरण कराना होगा और वहां शिक्षा विनियमन द्वारा निर्धारित योग्यता को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है - छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पंजीकरण न्यायाधिकरण का गठन और उक्त पंजीकरण न्यायाधिकरण द्वारा किए गए पंजीकरण अवैध और अवैध हैं - मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000।

अपील का निपटान करते हुए, न्यायालय ने

निर्णीत किया: 1. मध्य प्रदेश के पूर्ववर्ती राज्य द्वारा खोला गया पहला रजिस्टर क्षेत्रीय संबंध के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के पहले रजिस्टर के रूप में माना जाएगा, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक और पहले रजिस्टर खोलने की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप, फार्मेसी एक्ट की धारा 30 के तहत पंजीकरण न्यायाधिकरण के गठन की आवश्यकता नहीं है। जहां तक नवीकरण का सवाल है, एक बार मध्य प्रदेश के पूर्ववर्ती राज्य द्वारा तैयार पहले रजिस्टर को छत्तीसगढ़ राज्य का भी पहला रजिस्टर माना गया है, तो छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल को धारा 32(2) के तहत या कानून के अनुसार नवीकरण करने से कोई रोक नहीं है। [पैरा 9, 10][236-ई-एफ]

भारतीय फार्मेसी परिषद बनाम डॉ. आत्माराम दरियानी और ओआरएस।

नागरिक अपीलीय अधिकार क्षेत्र: 2017 की सिविल अपील संख्या 8382.

जबलपुर उच्च न्यायालय के 24.07.2002 के निर्णय और आदेश से, रिट याचिका संख्या 1472/2002 में।

मनींदर सिंह, एएसजी, ए. मरियारपुतम, अजीत कृ. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता। सुश्री अरुणा माथुर, युसूफ खान, अवनीश अरपुतम, सुश्री अनुराधा अरपुतम (एम/एस अरपुतम, अरुणा एंड कंपनी के लिए), सुश्री बीना गुप्ता, प्रभास बजाज, रोहित राठी, अक्षय अमृतांशु, रतन कुमार चौधरी, ए. पी. मयी, कुमार परिमल, ए. सेल्विन राजा, मिश्रा सौरभ, अंकित कृ. लाल, सुश्री वंशजा शुक्ला, सी. डी. सिंह, सुश्री साक्षी कक्कड़, वरिंदर कुमार शर्मा, मोहम्मद शाहिद हुसैन, अशोक माथुर, बी. के. सतीजा, अधिवक्ता उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय **एन. वी. रमना, जे.** द्वारा दिया गया। 1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील 24 जुलाई, 2002 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ है। उक्त निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी, जिसमें छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल को मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 ("एमआरओए" संक्षेप में) के तहत पुनर्गठन से पहले दिए गए पंजीकरण के नवीनीकरण की प्रक्रिया से रोक दिया गया था। सी.ए. नंबर 8121/2004 में एक अलग निर्णय द्वारा, हमने फार्मेसी अधिनियम, 1948 और बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के विभिन्न प्रावधानों के संदर्भ में कुछ निर्देश देकर एक अन्य संबंधित मामले का निपटारा किया। उस मामले में, मुद्दा यह था कि क्या झारखंड का नया राज्य फार्मेसी अधिनियम की धारा 30 के तहत फार्मासिस्टों का पहला रजिस्टर तैयार करने के लिए फिर से अभ्यास कर सकता है, जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा 84 और 85 के अनुसार है, जो पूर्ववर्ती बिहार द्वारा बनाए गए कानूनों के समान है और नए राज्य झारखंड में शामिल क्षेत्रों पर लागू होता है। वहां स्थापित कानून और कुछ निष्कर्ष, जो प्रासंगिक हैं, इस अपील पर भी लागू होंगे। हालांकि, तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में अंतर को ध्यान में रखते हुए, हम इस अपील को इस अलग आदेश द्वारा निपटाने का प्रस्ताव रखते हैं।

3. फार्मेसी एक्ट के लागू होने के बाद, मध्य प्रदेश राज्य ने प्रथम रजिस्टर तैयार किया। 1953 में, फार्मेसी काउंसिल ने शिक्षा विनियम बनाए जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया, नवीनतम 11.07.1992 को अधिसूचित शिक्षा विनियम, 1991 है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर किया गया और पुनर्गठन अधिनियम की धारा 78 और 79 कानूनों के क्षेत्रीय विस्तार और कानूनों को अनुकूल बनाने की शक्ति से संबंधित हैं। यह उल्लेखनीय है कि इन दो प्रावधानों के कारण, पुनर्गठन से पहले मध्य प्रदेश राज्य द्वारा बनाए गए कानून नए राज्य छत्तीसगढ़ में शामिल क्षेत्रों पर भी लागू होते रहेंगे।

4. छत्तीसगढ़ राज्य ने 01.03.2001 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें पंजीकरण न्यायाधिकरण के गठन का दावा किया गया था। उक्त न्यायाधिकरण ने फार्मेसी एक्ट की धारा 31 के तहत निर्धारित योग्यता के अनुसार फार्मासिस्टों के प्रथम रजिस्टर की तैयारी के लिए पंजीकरण करने का प्रयास किया। भारत की फार्मेसी काउंसिल, अपीलकर्ता ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार के सचिव और पंजीकरण न्यायाधिकरण के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर 01.03.2001 की अधिसूचना को वापस लेने, धारा 32(2) के तहत किए गए पंजीकरणों को रद्द करने और छत्तीसगढ़ राज्य के फार्मासिस्टों का रजिस्टर मध्य प्रदेश के फार्मासिस्टों के

रजिस्टर से विभाजित कर बनाने का अनुरोध किया। अपीलकर्ता ने छत्तीसगढ़ के लिए राज्य फार्मेसी काउंसिल के गठन का भी अनुरोध किया।

5. इस बीच, पहले प्रतिवादी डॉ. आत्माराम दरियानी, मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने रिट याचिका संख्या 1472/2002 दायर की, जिसमें छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल के खिलाफ निषेधाज्ञा की रिट की मांग की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल को उन फार्मासिस्टों का पंजीकरण नवीनीकरण करने के कार्य से रोका गया, जो छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल के साथ पहले पंजीकृत नहीं थे। उच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करते हुए, धारा 30 और 34 के आलोक में, रिट याचिका को अनुमति दी और निम्नलिखित अवलोकन किया:

> "अन्यथा भी, यह अधिनियम की धारा 30 और 34 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल उन व्यक्तियों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कर सकता जिनके नाम छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल द्वारा बनाए गए प्रथम रजिस्टर में दर्ज नहीं किए गए हैं। नवीनीकरण का अधिकार मेरी राय में केवल उन फार्मासिस्टों के संबंध में छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपने नाम उस काउंसिल में दर्ज कराने का विकल्प चुना है। एमपी काउंसिल का अधिकार क्षेत्र उन पर है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित नहीं किया है। मेरी राय में, नवीनीकरण का अधिकार प्राप्त करने के लिए, प्रथम रजिस्टर में प्रविष्टि आवश्यक है। पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, प्रतिवादी संख्या 4/5 द्वारा इस कार्यवाही को करना आवश्यक हो गया है। मेरी राय में, भले ही प्रारंभिक पंजीकरण एमपी फार्मेसी काउंसिल द्वारा दिया गया हो, लेकिन जिस तारीख को छत्तीसगढ़ में फार्मेसी काउंसिल का गठन हुआ और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, उसके बाद की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ काउंसिल पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकती है जिस तारीख को फार्मासिस्टों का प्रविष्टि प्रथम रजिस्टर में की गई है छत्तीसगढ़ काउंसिल द्वारा।
>
> उपरोक्त के मद्देनजर; यह निर्देशित है कि छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल द्वारा दिए गए किसी भी पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करेगा जो छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल के प्रथम रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है। परिस्थितियों में, लागतें पक्षों पर हैं।"

6. इस अपील में मुख्य रूप से भारत की फार्मेसी काउंसिल द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियों और निर्देशों का दुरुपयोग किया जा सकता है और इससे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए फार्मेसी एक्ट की धारा 30 के तहत प्रथम रजिस्टर की तैयारी को फिर से वैधता मिल जाएगी। अपीलकर्ता के अनुसार, इससे उन फार्मासिस्टों का पंजीकरण हो जाएगा जो केवल धारा 31 के तहत योग्यता को पूरा करते हैं, जबकि फार्मेसी एक्ट की धारा 32 के अनिवार्य प्रावधानों की उपेक्षा की जा रही है।

7. हमने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है। मुख्य प्रश्न जो हमारे विचार की आवश्यकता है वह यह है कि क्या नया छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम रजिस्टर की तैयारी के उद्देश्य से धारा 30 के तहत पंजीकरण न्यायाधिकरण का गठन करने के लिए सक्षम है; और दूसरा, क्या पंजीकरण न्यायाधिकरण उन फार्मासिस्टों के पंजीकरण के नवीनीकरण का कार्य करने के लिए सक्षम था जो पहले से ही मध्य प्रदेश के पूर्ववर्ती राज्य द्वारा तैयार फार्मासिस्टों के प्रथम रजिस्टर में शामिल हैं।

8. जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, हमने सी.ए. नंबर 8121/2004 में अपने निर्णय में इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया है। हम निम्नलिखित अनुच्छेदों का उल्लेख कर सकते हैं:

> **35.** जब भारतीय राष्ट्र के हिस्से के रूप में एक राज्य का पुनर्गठन किया जाता है, तो कानून के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित तीन चीजें होंगी: (i) मौजूदा राज्य (मूल राज्य) जिसने विभिन्न कानून बनाए, वह अस्तित्व में रहेगा; (ii) कुछ क्षेत्रों को स्थानांतरित करके बनाए गए नए राज्य को कानूनों की प्रयोज्यता के उद्देश्य से मूल राज्य का क्षेत्र माना जाएगा; और (iii) मूल राज्य द्वारा बनाए गए कानून नए राज्य पर तब तक लागू होते रहेंगे जब तक उन्हें नए राज्य के संदर्भ में सक्षम विधायिका द्वारा संशोधित या परिवर्तित नहीं किया जाता और परिभाषा खंड में परिभाषित 'कानून' वह कानून होगा जो मौजूदा राज्य में लागू था जो नए बने राज्य में लागू होगा।
>
> **36.** दोहराव के जोखिम पर, हम उल्लेख कर सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्रों का परिसीमन, राज्यों का विलय, क्षेत्र का कमी या वृद्धि कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में लागू 'स्वच्छ स्लेट' का सिद्धांत संविधान[1] के अनुच्छेद 3 के तहत पुनर्गठन होने पर लागू नहीं होता है। पुनर्गठित राज्यों का सामान्यतः *'टैबुला रसा'* के रूप में शुरुआत नहीं होती है, बल्कि वे पूर्ववर्ती राज्यों के उत्तराधिकारी होते हैं। बी.आर.ए.ओ के तहत, झारखंड को बिहार से विभाजित किया गया था और 15.11.2000 को दो अलग-अलग राज्यों का गठन हुआ। यदि विभाजन के दिन लागू कानून समाप्त हो गए होते, तो एक अराजक स्थिति उत्पन्न होती क्योंकि नवगठित राज्य कानूनों के बिना राज्य बन जाता। ऐसी स्थिति से बचने के लिए, बी.आर.ए.ओ की धारा 84 और 85 जैसे प्रावधान लागू किए गए हैं ताकि निरंतरता बनाए रखी जा सके, और साथ ही राज्यों को केवल आदेश जारी करके आवश्यकतानुसार संशोधन और अनुकूलन करने का अधिकार दिया जा सके, और उसके बाद कानून के माध्यम से।
>
> **37.** पहले परिभाषित किए गए अनुसार 'कानून' में 'अन्य साधन जिनमें कानून की शक्ति है' भी शामिल हैं। 'शामिल हैं' शब्द के उपयोग को देखते हुए, धारा 2(एफ) के तहत 'कानून' की परिभाषा का व्यापक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए। उपरोक्त चर्चा के अनुसार, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि बिहार द्वारा तैयार किया गया प्रथम रजिस्टर बी.आर.ए.ओ की धारा 2(एफ) के तहत कानून की शक्ति रखता है।
>
> **38.** उपरोक्त के मद्देनजर, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब पंजीकरण न्यायाधिकरण द्वारा तैयार किया गया फार्मासिस्टों का प्रथम रजिस्टर बिहार सरकार द्वारा धारा 30 की उपधारा (4) के तहत प्रकाशित किया गया, तो वह निष्कर्षात्मक है और समावेशों के माध्यम से किसी भी संशोधन को भारतीय फार्मेसी काउंसिल द्वारा शिक्षा विनियमों के निर्माण तक किया जा सकता है। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी धारा 31 में निर्धारित योग्यता को ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि, शिक्षा विनियमों के लागू होने के बाद और बाद के पंजीकरण के समय, सरकार को अनिवार्य रूप से शिक्षा विनियमों का पालन करना होगा। कोई भी व्यक्ति जो शिक्षा विनियमों के अनुसार योग्यता को पूरा नहीं करता है, वह फार्मेसी रजिस्टर में प्रवेश पाने का हकदार नहीं होगा। इस दृष्टिकोण से, जब बिहार राज्य को प्रथम रजिस्टर को फिर से तैयार करने से रोका गया है, तो झारखंड राज्य को भी प्रथम रजिस्टर को फिर से तैयार करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में झारखंड उच्च न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचा है।

---

[1] ऊपर अर्थ का उपसर्ग, 13 पर

39. इस स्तर पर हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय ने प्रथम रजिस्टर के संदर्भ में बी.आर.ए.ओ की धारा 84 के प्रभाव को पूरी तरह से नहीं माना, हालांकि यह निष्कर्ष निकाला कि प्रथम रजिस्टर को फिर से तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी। झारखंड राज्य के लिए प्रथम रजिस्टर वह है जो अविभाजित बिहार के लिए पहले से तैयार किया गया था, जिसमें सभी फार्मासिस्ट शामिल हैं जो अब झारखंड राज्य में रह रहे हो सकते हैं।

40. निर्णय के पहले भाग में हमने बिहार द्वारा तैयार किए गए प्रथम रजिस्टर पर धारा 84 के प्रभाव पर विचार किया है। यह विशेष रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। जैसा कि हमने पहले ही देखा है, जब भी एक नवगठित राज्य कानून को अपनाकर प्रथम रजिस्टर को फिर से तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करना चाहता था, तो ऐसे प्रावधान विशेष रूप से बनाए गए थे। हम ऐसे प्रावधानों को उद्धृत कर सकते हैं:

आंध्र प्रदेश [आंध्र ए.एल.ओ., 1954 (01.10.1953)]

33A. आंध्र प्रदेश राज्य के फार्मासिस्टों के रजिस्टर की तैयारी के लिए विशेष प्रावधान.- (1) इस अध्याय में कुछ भी निहित होने के बावजूद, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति (जिसे आगे अधिकृत अधिकारी कहा जाएगा) यहाँ प्रस्तुत किए गए अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक अलग फार्मासिस्ट रजिस्टर तैयार करेगा और वह रजिस्टर सभी उद्देश्यों के लिए इस अधिनियम के तहत तैयार रजिस्टर माना जाएगा।

महाराष्ट्र [एस.ओ. 2814, भारत के राजपत्र में प्रकाशित, 19.08.1964, भाग II, खंड 3(ii), अतिरिक्त, पृष्ठ 717 (722, 723)]

29A. महाराष्ट्र राज्य और गुजरात राज्य के फार्मासिस्टों के रजिस्टर के संबंध में प्रावधान। - (1) जिस दिन बंबई राज्य फार्मेसी परिषद (पुनर्गठन) आदेश, 1964, अंतर-राज्य निगम अधिनियम, 1957 की धारा 4 के तहत बनाया गया, प्रभाव में आता है, के बाद जल्द से जल्द, महाराष्ट्र राज्य फार्मेसी परिषद, धारा 30, 31 और 32 में निहित किसी भी चीज के बावजूद, महाराष्ट्र राज्य के लिए फार्मासिस्टों का एक रजिस्टर तैयार करेगी और उसके बाद उसका रखरखाव करेगी। यह रजिस्टर निम्नलिखित नामों को शामिल करेगा-

(a) सभी फार्मासिस्ट जो पूर्व बंबई राज्य के फार्मासिस्टों के रजिस्टर में शामिल हैं, जो धारा 29 के तहत ठीक से तैयार और रखरखाव किए गए हैं जिनके आवासीय पते जैसा कि उसमें दिखाया गया है, गुजरात राज्य के क्षेत्रों में नहीं आते हैं, या 1 नवंबर, 1956 को मैसूर या राजस्थान राज्य में स्थानांतरित किए गए पूर्व बंबई राज्य के क्षेत्र में नहीं आते हैं, और इसी तरह से तैयार और रखरखाव किए गए पूर्व मध्य प्रदेश राज्य के रजिस्टर में शामिल हैं, जिनके आवासीय पते जैसा कि उसमें दिखाया गया है, महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्रों में आते हैं:

प्रदत्त कि, पूर्व मध्य प्रदेश राज्य के फार्मासिस्टों के रजिस्टर में फार्मासिस्टों के नाम तब तक महाराष्ट्र राज्य के रजिस्टर में शामिल नहीं किए जाएंगे जब तक कि महाराष्ट्र राज्य फार्मेसी परिषद इस राज्य के विदर्भ क्षेत्र में धारा 19-ए की उपधारा (5) के खंड (2) के तहत कार्य करना और संचालन शुरू नहीं करती;

41. जहां तक बी.आर.ए.ओ का संबंध है, हालांकि अधिनियम को बी.आर.ए.ओ की धारा 84 और 85 के तहत अपनाया गया था, कोई ऐसा संशोधन नहीं किया गया है। इस दृष्टिकोण से धारा 84 को लागू करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पूर्व बिहार द्वारा तैयार किया गया प्रथम रजिस्टर झारखंड के लिए प्रथम रजिस्टर माना जाएगा और जारी रहेगा। हालांकि, यह झारखंड को धारा 32 और 32ए और 32बी के अनुसार बाद के पंजीकरण करने से नहीं रोकता है। ऐसी स्थिति में झारखंड के संबंधित प्राधिकारी को भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित किए गए शिक्षा विनियमों का पालन करना होगा।

42. बी.आर.ए.ओ की धारा 86 स्पष्ट रूप से इस न्यायालय को कानून की व्याख्या करने का अधिकार देती है ताकि धारा 84 और 85 को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। बी.आर.ए.ओ के सभी प्रावधानों पर विचार करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पूर्व बिहार राज्य के फार्मासिस्टों के प्रथम रजिस्टर में शामिल सभी फार्मासिस्ट, जिनके आवासीय पते, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, झारखंड राज्य के क्षेत्र में आते हैं, उन्हें झारखंड के प्रथम रजिस्टर का हिस्सा माना जाएगा। रजिस्टर में अतिरिक्त नामों का भविष्य में समावेश फार्मेसी अधिनियम की धारा 32 (2) के अनुसार किया जाना है। हम आगे आशा करते हैं कि झारखंड राज्य निकट भविष्य में एक राज्य परिषद के गठन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा, यदि पहले से नहीं उठाए गए हैं। तदनुसार, झारखंड राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द करने की सीमा तक उच्च न्यायालय का आदेश, दिनांक 12.11.2001, धारा 30 के तहत पंजीकरण न्यायाधिकरण का गठन और धारा 31 के तहत आवेदन आमंत्रित करने वाला विज्ञापन, बरकरार रखा जाता है।

43. उपरोक्त विश्लेषण और चर्चा के प्रकाश में, हम निम्नलिखित आदेश देते हैं-

a. पूर्व बिहार राज्य द्वारा तैयार किया गया प्रथम रजिस्टर नवगठित झारखंड राज्य और बिहार राज्य के लिए प्रथम रजिस्टर माना जाएगा।

b. पूर्व बिहार राज्य द्वारा तैयार किया गया प्रथम रजिस्टर पंजीकरण के समय फार्मासिस्टों द्वारा प्रदान किए गए आवासीय पते के साथ क्षेत्रीय संबंध के आधार पर विभाजित किया जाएगा।

c. झारखंड राज्य एक राज्य परिषद गठित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है।

d. वे फार्मासिस्ट जो केंद्रीय फार्मेसी परिषद द्वारा बनाई गई शिक्षा विनियम के लागू होने से पहले पूर्व बिहार राज्य के प्रथम रजिस्टर में पंजीकृत हैं, और जो उस राज्य में अभ्यास नहीं करना चाहते जहां उनके आवासीय पते आते हैं, वे फार्मेसी अधिनियम की धारा 32 (2) के अनुसार खुद को दूसरे राज्य में पंजीकृत कराने के लिए स्वतंत्र हैं। यहां हम स्पष्ट करते हैं कि ऐसे फार्मासिस्टों को जिनके नाम पूर्व बिहार राज्य द्वारा तैयार किए गए प्रथम रजिस्टर में पंजीकृत हैं, उन्हें झारखंड

राज्य में धारा 32(2) के तहत औपचारिक रूप से पंजीकरण कराना आवश्यक है और उन्हें शिक्षा विनियम द्वारा निर्धारित योग्यता को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।

उदाहरण 1- यदि 'A' का नाम पूर्व बिहार राज्य के प्रथम रजिस्टर में पंजीकृत है। वह फार्मेसी अधिनियम की धारा 32 (2) के अनुसार अपना नाम झारखंड राज्य में पंजीकृत कराने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा 'A' को शिक्षा विनियम द्वारा निर्धारित योग्यता को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।

9. हमारे द्वारा उपर्युक्त निर्धारित कानून के अनुसार, पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य द्वारा खोला गया प्रथम पंजीकरण राज्य छत्तीसगढ़ के लिए प्रथम पंजीकरण माना जाएगा, जो क्षेत्रीय संबंध पर आधारित है। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक और प्रथम पंजीकरण खोलने की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप, फार्मेसी अधिनियम की धारा 30 के तहत पंजीकरण ट्रिब्यूनल का गठन करने की आवश्यकता नहीं है।

10. जहां तक नवीकरण का सवाल है, एक बार जब पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य द्वारा तैयार किया गया प्रथम पंजीकरण छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पंजीकरण के रूप में माना जाता है, तो छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल को धारा 32(2) या कानून के अनुसार नवीकरण करने से कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है।

11. उपरोक्त के मद्देनजर, हम इस अपील को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के साथ निस्तारित करते हैं:

a. पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य द्वारा तैयार किया गया प्रथम पंजीकरण नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य और मध्य देश राज्य के लिए प्रथम पंजीकरण के रूप में माना जाएगा।

b. पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य द्वारा तैयार किया गया प्रथम पंजीकरण पंजीकरण के समय फार्मासिस्टों द्वारा प्रदान किए गए आवासीय पते के आधार पर क्षेत्रीय संबंध के आधार पर विभाजित किया जाएगा।

c. वे फार्मासिस्ट जो पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम पंजीकरण में पंजीकृत हैं, केंद्रीय फार्मेसी काउंसिल द्वारा बनाए गए शिक्षा नियमावली के लागू होने से पहले, और जो उस राज्य में अभ्यास नहीं करना चाहते जहां उनका आवासीय पता है, उन्हें फार्मेसी अधिनियम की धारा 32(2) के अनुसार अन्य राज्य में खुद को पंजीकृत करने की स्वतंत्रता है। यहां हम स्पष्ट करते हैं कि वे फार्मासिस्ट जिनके नाम पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य द्वारा तैयार किए गए प्रथम पंजीकरण में पंजीकृत हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य में फार्मेसी अधिनियम की धारा 32(2) के तहत पंजीकरण प्राप्त करने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन करना होगा और उन्हें शिक्षा नियमावली द्वारा निर्धारित योग्यता को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।

उदाहरण 1 - यदि 'A' का नाम पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम पंजीकरण में पंजीकृत है, तो वह फार्मेसी अधिनियम की धारा 32(2) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अपना नाम पंजीकृत करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त, 'A' को शिक्षा नियमावली के तहत निर्धारित योग्यता को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।

d. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पंजीकरण ट्रिब्यूनल का गठन और उक्त पंजीकरण ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए पंजीकरण अमान्य और अवैध हैं।

12. इस प्रकार, इस अपील को उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार निस्तारित किया जाता है। लागत पर कोई आदेश नहीं होगा।

देविका गुज्जर अपील निस्तारित की गई।

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।**